

प्रेषक,

डी0एस0 गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 04 अगस्त, 2015

विषय:- नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न सर्वे हेतु Statistic for HR and Assessment (USHA)scheme के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1755/IV(1)-2010-29(JnNURM)/08, दिनांक 15.10.2010 एवं शासनादेश संख्या: 777/IV(2)-श0वि0-11-29(JnNURM)/08, दिनांक 24.06.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से Statistic for HR and Assessment (USHA)scheme के अन्तर्गत निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न सर्वे कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या: 23/8/2007-SE(NBO)-Part, दिनांक 14.03.2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा HSUI Cell हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि रु. 2.40 लाख अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि USHA योजनान्तर्गत Housing Start-Up Index (HSUI) Cell हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किस्त की धनराशि ₹2.40 लाख (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि ₹2.40 लाख (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर नगर निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) उक्त धनराशि नगर निगम, देहरादून को योजनान्तर्गत धनराशि की आवश्यकता एवं प्रगति की पुष्टि के उपरान्त ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (vi) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण करते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (vii) स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- (viii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-02-आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना यू०आई०डी०एस०एम०पी०-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 273/XXVII(2)/2015, दिनांक 21.07.2015 में प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28-03-2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.1500.813.14 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

सं० 775(1)/IV(2)-शा०वि०-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(आडिट)/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-1/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।